[Mr. Speaker]

public owned or controlled units required for ensuring supply of wholesome vanaspati and refined edible oils, nutritions foods and other consumer commodities to the public at reasonable prices and thereby to give effect to the policy of the State towards security the principles specified in clauses (b) and (c) of article 30 of the Constitutions."

The motion was adopted.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : I introduce** the Bill.

12.29 hrs.

STATEMENT FOR IMMEDIATE LEGILATIONS BY THE GANESH FLOUR MILLS COMPANY LTD. (ACQUISITION AND TRASFER OF UNDERTAKINGS) ORDINANCE, 1984.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) giving reasons for immediate leg slation by the Ganesh Flour Mills Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance, 1984.

12.30 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to fix Support Price of wheat at Rs. 204/- per quintal.

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, शीत लहर के कारण फसलों की खराबी तो है ही परन्तु बिजली व पानी का अभाव, फर्टीलाइजर और कीटनाशक दवाइयों का महंगा तथा मिलावटी होना, अकाल का कारण बन गया है। ओलावृष्टि, शीत लहर और दूसरे कारणों से जो नरमें और दूसरी फसलें खराब हुई हैं उन का मुआवजा हरियाणा को अभी तक नहीं मिला है और माल व आबियाना भी वसूल हुआ है। यह बहुत ज्यादती है। नरमें में मुआवजा दिया जाए।

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

किसानों को कम दर पर बिजली दी जाए। बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उन फसलों का मुआवजा तुरन्त दिया जाए। गेहूं की फसल की सपोर्ट प्राईस सरकार ने रखी है वह किसानों के साथ घोर अन्याय है। कम से कम 204 रुपये प्रति क्विन्टल गेहू की कीमत होनी चाहिए। जो कि सरकार विदेश से गेहूं मंगवाने पर देती है तो फिर भारत के किसानों को इतनी कीमत क्यों नहीं दी जाए। सरकार तुरन्त गेहूं की आधार कीमत 204 रुपये मुकर्रर करे। 17 करोड़ 7 लाख रु जो हरियाणा सरकार को बाढ़ नियंत्रण के लिए दिये है उसका अभी तक हरियाणा सरकार ने उपयोग शुरू नहीं किया है। परंतु आदेश दिये जाएं कि बाढ़ मेंध को स्थायी तौर पर रोकने के लिए बांध व खुदाई और ट्यूबवेल का काम चालू करें।

(ii) Demand to Increase Shipment Capacity of Paradip Port.

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (Cuttack) : A serious situation has arisen in the Chaibasa region in Bihar following the closure of as many as 75 iron ore mines owned and managed by private companies. There are 91 iron ore mines in that area, 16 of which are

**Introduced with the recommendation of the President.